प्रस्तावना

भारत की स्वास्थ्य चुनौतियों में काफी विविधता है। विभाग का प्रयास सभी नागरिकों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करना है। मेरा प्रस्तावना नोट वर्ष 2015–16 के दौरान विभाग की कुछ प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करता है।

ekr` ,o uotkr f'k'kqvk e fVVul dk mUeyu ¼,eVh,ub½

मातृ एवं नवजात शिशुओं में टिटेनस के उन्मूलन (एमटीएनई) का अर्थ है प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष प्रति हजार जीवित शिशु–जन्म पर नवजात शिशुओं में टिटेनस के एक से कम मामले। भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दिसम्बर, 2015 की वैश्विक स्तर पर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्धारित तिथि से पहले ही मातृ एवं नवजात शिशुओं में टिटेनस के उन्मूलन (एमटीएनई) की स्थिति प्राप्त होने की पुष्टि हो गई है। वर्ष 2015 में मातृ एवं नवजात शिशुओं में टिटेनस के उन्मूलन (एमटीएनई) की इस उपलब्धि को प्राप्त करने पर डब्ल्यूएचओ के सहायक महानिदेशक, डॉ. फ्लेविया बुस्त्रेओ ने भारत को औपचारिक रूप से बधाई दी है।

fe'ku bæ/kuq"k

इस मिशन का लक्ष्य नेमी प्रतिरक्षण चक्रों के दौरान छोड़ दिए गए या छूट गए बच्चों तक पहुंचना है। मिशन का लक्ष्य वर्ष 2020 तक कम–से–कम 90% बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षण प्रदान करने का है। पहला चरण 210 उच्च फोकस जिलों में आरंभ किया गया था। 75 लाख से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया था, जिनमें से 20 लाख बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया था और लगभग 21 लाख गर्भवती महिलाओं को टिटेनस टॉक्सॉइड टीका लगाया गया था। दूसरा चरण देश के 352 जिलों में आरंभ किया गया था जिनमें से चरण–1 के 73 उच्च फोकस जिले थे। जनवरी, 2016 तक 75 लाख से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया था, जिनमें से 15 लाख बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया गया था और 14 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को टिटेनस टॉक्सॉइड टीका लगाया गया था।

u, Vhd

भारत पोलियोमुक्त हो गया है लेकिन इस स्थिति को बनाए रखने के लिए 30 अक्टूबर, 2015 को निष्क्रिय पोलियो टीका (इनएक्टिवेटिड पोलियो वैक्सीन) आरंभ की गई थी। इस टीके को आरंभ में 6 राज्यों – बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और पंजाब में आरंभ किया गया है। इससे प्रतिवर्ष 2.7 करोड़ बच्चों को लाभ मिलेगा।

15–65 वर्ष के आयु–समूह में वयस्क जेई टीकाकरण हेतु असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के रोगियों की अधिक संख्या वाले 21 जिलों की पहचान की गई है। इससे वयस्कों में भी जापानी इंसेफ्लाइटिस के कारण होने वाली मौतों और रुग्णता में कमी आएगी।

xgu vfrlkj fu;=.k i[kokMk ¼27 tqykb& 8 vxLr] 2015½

गहन अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा (आईडीसीएफ) 27 जुलाई से 8 अगस्त, 2015 तक मनाया गया था जिसका लक्ष्य ओआरएस, जिंक डिस्पर्सिबल टैबलेट जैसी अनिवार्य जीवनरक्षक वस्तुओं की कवरेज तथा अतिसार के दौरान

बच्चों को खिलाने की उपयुक्त परिपाटी अपनाने में सुधार लाना है। ओआरएस को 6.6 करोड़ बच्चों के घरों में पहले ही पहुंचा दिया गया था ताकि समय रहते अतिसार का उपचार किया जा सके। पखवाड़े के दौरान 36.3 लाख बच्चों का जिंक और ओआरएस, दोनों के द्वारा उपचार किया गया था।

jk"Vªh; cky LokLF; dk;Øe ¼vkjch,l d½

आरबीएसके के तहत बच्चों की जांच –जन्म के समय विकृति, रोग, कमी, निशक्तता सहित विकासात्मक विलंब का शीघ्र पता लगाने के माध्यम से बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और परिवारों के फुटकर खर्च में कमी लाने के उद्देश्य से बाल स्वास्थ्य जांच और त्वरित कार्यकलाप सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस कार्यकलाप के तहत अब तक 9774 दलों द्वारा 10.66 करोड़ बच्चों की जांच की गई (वित्त वर्ष 2014–15) और उपर्युक्त 4 कमियों के उपचार हेतु 51.78 लाख बच्चों को रैफर किया गया तथा 30 स्वास्थ्य स्थितियों हेतु 22.18 लाख बच्चों का उपचार किया गया।

n{k

स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों के कौशल में सुधार लाने के लिए तथा गुणवत्तायुक्त (प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य) आरएमएनसीएच़ए सेवाएं प्रदान करने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 5 राष्ट्रीय कौशल प्रयोगशालाओं 'दक्ष' की स्थापना की है। ये कौशल प्रयोगशालाएं कौशल प्रयोगशाला के निर्माण और राज्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने में भी सहयोग तथा मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। राष्ट्रीय कौशल प्रयोगशालाएं सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबद्ध की जा रही हैं ताकि राष्ट्रीय कौशल प्रयोगशाला का इष्टतम उपयोग हो सके।

ifjokj fu;kstu

विकल्पों की संख्या में विस्तार : राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में अब 3 नए विकल्पों को शामिल किया जा रहा है अर्थात् इंजेक्टेबल डीएमपीए : औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जन–स्वास्थ्य प्रणाली में इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक डीएमपीए को शामिल करने पर सहमत है; पीओपी : स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल तथा सेन्टक्रोमैन : सप्ताह में एक बार ली जाने वाली एक नॉन–हार्मोनल गोली।

प्रसव पश्चात् आईयूसीडी (पीपीआईयूसीडी) कार्यक्रम में निरंतर सुधार आ रहा है। वर्ष 2015–16 की तीसरी तिमाही में पीपीआईयूसीडी की स्वीकार्यता दर 15% तक बढ़ी है।

fd'kksj LokLF;

साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड सम्पूर्ण (डब्ल्यूआईएफएस), मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम तथा किशोरावस्था में गर्भधारण करने से संबंधित मुद्दों पर सम्प्रेषण सामग्री तैयार की गई है और राज्यों के साथ साझा की गई है।

देश के यूनिसेफ कार्यालय के सहयोग से डब्ल्यूआईएफएस हेतु गहन मीडिया अभियान चलाया गया है जिसमें किशोरों में पोषण और रक्ताल्पता के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को शामिल करने के अतिरिक्त सभी राज्यों के प्रमुख समाचारपत्रों में पोषण, रक्ताल्पता और डब्ल्यूआईएफएस कार्यक्रम पर लेख तथा अपने विषय के विशेषज्ञों के आलेखों का प्रकाशन शामिल हैं।

dk;kdYi & tu LokLF; lfo/kk dnk dk ijLdkj nu d lc/k e ,d igy dk 'kHkkjHk

जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सफाई, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण की परिपाटी को प्रोत्साहित करने के लिए कायाकल्प – पहल का शुभारंभ किया गया है। इस पहल के तहत जन स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों की सराहना की जाएगी तथा ऐसे जन स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र जो सफाई, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण के नवाचार मानकों को पूरा करते हुए उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन्हें पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।

निःशुल्क औषधि सेवा पहलः एनएचएम – निःशुल्क औषधि सेवा पहल के तहत निःशुल्क औषधि के प्रावधान हेतु तथा औषधि प्रापण, गुणवत्ता आश्वासन, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली, प्रशिक्षण व शिकायत

निवारण हेतु प्रणालियों की स्थापना के लिए राज्यों को पर्याप्त निधि प्रदान की जा रही है बशर्ते कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कुछ विशेष शर्तों को पूरा करें। एनएचएम – निःशुल्क औषधि सेवा पहल के लिए प्रचालनात्मक दिशा–निर्देश भी 02 जुलाई, 2015 को राज्यों को जारी कर दिए गए हैं।

निःशुल्क नैदानिक जांच सेवा पहलः इस पहल हेतु प्रचालनात्मक दिशा–निर्देश 02 जुलाई, 2015 को साझा किए गए हैं। 5 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू व कश्मीर तथा त्रिपुरा ने राष्ट्रीय दिशा–निर्देशों के अनुसार इस मॉड्यूल को अपनाया है।

किलकारी और मोबाइल अकादमीः प्रसवपूर्व परिचर्या (एएनसी), संस्थागत प्रसव, प्रसव पश्चात् परिचर्या (पीएनसी) तथा प्रतिरक्षण के महत्व के संबंध में गर्भवती महिलाओं, बच्चों के माता–पिता तथा फील्ड वर्करों के बीच पर्याप्त जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 6 राज्यों अर्थात् उत्तराखण्ड, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान (एचपीडी) और मध्य प्रदेश (एचपीडी) में 15 जनवरी, 2016 को किलकारी का प्रथम चरण आरंभ किया गया है। किलकारी एक इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पोंस (आईवीआर) है जिसमें गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से लेकर शिशु का एक वर्ष का होने तक, उचित समय पर गर्भावस्था, शिशु के जन्म तथा शिशु की देखभाल के संबंध में 72 ऑडियो मैसेज सीधे परिवार के मोबाइल फोन पर भेजे जाते हैं। 4 राज्यों अर्थात् उत्तराखण्ड, झारखण्ड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 15 जनवरी, 2016 को मोबाइल अकादमी का पहला चरण भी आरंभ किया गया था।

राष्ट्रीय एंटी–टीबी औषधि प्रतिरोध सर्वेक्षण की शुरूआतः समुदाय में बहु–औषधीय प्रतिरोधक टीबी भार का बेहतर अनुमान उपलब्ध कराने के लिए 13 टीबी औषधियों के लिए औषधि प्रतिरोध सर्वेक्षण शुरु किया गया था। 5214 रोगियों के नमूनों के आकार वाला यह विश्व का अब तक सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। इसके परिणाम 2016 तक आने का अनुमान है।

jDrdk"k

सरकार ने रक्त बैंकों और रक्त भंडारण इकाईयों के लिए एक केन्द्रीयकृत ई–रक्तकोष अनुप्रयोग विकसित किया है ताकि कार्यप्रवाह को स्वचालित किया जा सके और रक्त बैंकों से संबंधित नागरिक–केन्द्रित सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस अनुप्रयोग का शुरुआती दौर कुछ राज्यों में शुरु किया जा रहा है।

ghekXykfcukiFkht

हीमोग्लोबिनोपेथीज (थेलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया आदि) के निवारण तथा नियंत्रण हेतु व्यापक दिशा–निर्देश तैयार किए गए और राज्यों से साझा किए गए ताकि हीमोग्लोबिनोपेथीज संबंधित मामलों के समाधान के लिए राज्यों की सहायता और मदद की जा सके।

uokpkjk dk vf/kdr dju vkj lk>k dju d fy, ,d dUæh; ikVy

एनएचएम ने स्वीकृति हेतु मूल्यांकन एवं सिफारिशों के लिए अपलोड किए जाने वाले उत्पादों और प्रक्रियाओं में स्वास्थ्य क्षेत्र के नवाचारों को सक्षम बनाने हेतु एक मंच तैयार किया है। सर्वश्रेष्ठ नवाचारों में से कुछ को राज्यों के साथ अच्छे और प्रतिकृति योग्य पद्धतियों पर उनके वार्षिक सम्मेलन में साझा किया जाएगा।

Vhch&,pvkboh lg&lØfer jkfx;k d fy, ,dy f[kMdh lok,

आरएनटीपीसी नाको के सहयोग से और भारत के लिए डब्ल्यूएचओ के राष्ट्र कार्यालय से तकनीकी सहायता सहित वर्तमान में भारत के पांच राज्यों में चुनिंदा 30 उच्च भार एआरटी केन्द्रों पर अप्रैल 2015 से एक परियोजना "गहन टीबी मामलों की पहचान और उचित उपचार" कार्यान्वित कर रहा है। यह परियोजना टीबी और एचआईवी हेतु एकल खिड़की सेवा प्रदानगी सहित एचआईवी एड्स के साथ रह रहे लोगों (पीएलएचए) में टीबी के बोझ को कम करने, सीबी एनएएटी सहित त्वरित निदानों, एआरटी केन्द्र पर एआईसी उपायों और नियत खुराक मिश्रण दैनिक चिकित्सा के लिए व्यापक कार्यनीतियों पर केन्द्रित है। दिसंबर, 2015 तक 18000 से अधिक रोगियों की जांच की गई और परियोजना के तहत 900 से अधिक रोगियों का उपचार किया गया।

lhMh,llhvk dk ln<hdj.k vkj b&xoul ykx djuk

सरकार ने देश में औषधि विनियामक ढ़ांचों को सुदृढ़ करने के लिए 1750 करोड़ रुपए की कुल लागत से एक योजना को स्वीकृति दी है, जिसे 2017–18 तक क्रियान्वित किया जाएगा। इसमें नई प्रयोगशालाओं को स्थापित करना, अतिरिक्त मानव संसाधनों का प्रावधान, विनियामकों के लिए प्रशिक्षण आकादमी, हमारे विनियामक ढांचों की क्षमता को काफी हद तक बढ़ाने के उद्देश्य सहित ई–गवर्नेंस द्वारा संगठन शामिल हैं।

पत्तनों/विमान पत्तनों पर सीडीएससीओ के कार्यालयों को 24x7 के आधार पर कार्यशील बनाया गया है। प्रत्येक प्रवेश बिंदु अर्थात सीमा शुल्क प्रवेश द्वार (आईसीईगेट) पर एकीकृत घोषणा के माध्यम से आवेदन पत्रों, प्रविष्टि बिल और पोत परिवहन बिल की इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुति के लिए आवश्यक आंकड़ों हेतु जांच सूची को सीमा शुल्क विभाग के साथ आदान–प्रदान किया है।

संगठन के व्यापक ई–गर्वेनेंस के लिए प्रक्रिया के भाग के रूप में, दिनांक 14.11.2015 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने ई–गवर्नेंस पोर्टल 'सुगम' (www.cdscoonline.gov.in) का उद्घाटन किया। इसमें औषधियों के आयात हेतु आवेदन संबंधी कार्य और औषधियों के पंजीकरण के साथ–साथ निजी प्रयोग हेतु थोड़ी औषधियों के आयात हेतु अनुमति शामिल है। इसके अतिरिक्त देश में नैदानिक परीक्षणों के लिए आवेदनों की ऑनलाइन प्रस्तुति हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणाली को भी आरंभ किया गया तथा http://otcams.gov.in के माध्यम से पणधारकों को सुलभ कराया गया है।

ih,e,l,lokb dh ixfr

चरण–I एवं II के तहत अमृतसर के जीएमसी और वाराणसी में अभिघात केन्द्र का उन्नयन कार्य पूरा हो गया है। जीएमसी, श्रीनगर में उन्नयन कार्य 99.5 प्रतिशत पूरा हो गया है।

चरण–III के तहत कार्यकारी एजेंसियों अर्थात एचएससीसी (I) और एचआईटीईएस तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच संस्था के बहिर्नियम पर हस्ताक्षर किया गया। चरण–III में सिविल निर्माण हेतु 39 डीपीआर में से 37 डीपीआर को अनुमोदन दे दिया गया है।

चरण–IV के तहत आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी (गुंटूर जिला), महाराष्ट्र के नागपुर और पश्चिम बंगाल के कल्याणी में तीन नए एम्स की स्थापना के लिए दिनांक 07.10.2015 को मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया गया है।

चरण–V के तहत पंजाब के भटिंडा में निर्माण स्थल को अंतिम रूप दे दिया गया है।

fpfdRlk f'k{kk

चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य व्यवसायिकों की उपलब्धता को बढ़ाने की योजना का पता लगाने हेतु केन्द्र सरकार ने अनेक पहल की हैं। 100 एमबीबीएस सीटों के साथ एम्स जैसे नए संस्थानों की स्थापना करना एक ऐसी ही पहल है। इसके अतिरिक्त सरकार उन जिलों, जहां मेडिकल कालेज नहीं है, में जिला अस्पतालों के उन्नयन द्वारा मेडिकल कालेजों की भी स्थापना कर रही है। यह योजना देश में चिकित्सा कॉलेजों की संख्या की असमानता को कम करने पर केन्द्रित है। अब तक 38 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं और 487 करोड़ रूपए की राशि निर्गत की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक चिकित्सा महाविद्यालय पहले से ही संचालित है। अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में पहली बार अपने चिकित्सा महाविद्यालय बने हैं। हम सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस सीटों में वृद्धि करने के लिए भी एक योजना चला रहे हैं। अब तक 1765 सीट सहित कुल 23 चिकित्सा महाविद्यालय अनुमोदित किए गए हैं। वर्ष के दौरान सरकार ने 18 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति भी दी है: 11 सरकारी और 7 गैर–सरकारी क्षेत्र में।

mip;k d rgr ub igy

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनआईसी के सहयोग से 'लाइव रजिस्टर' नामक एक प्रौद्योगिकी मंच

तैयार किया है। लाइव रजिस्टर में वर्तमान में प्रैक्टिस कर रही नर्सों से सम्बन्धित अद्यतन सूचना शामिल होगी। एएनएम और जीएनएम स्कूल स्थापित करने के लिए अब तक 219.803 करोड रू. और 532.0755 करोड रू. की राशि दी गयी है।

jk"Vªh; ,M~l fu;a=.k dk;ZØe ¼,u,lhih½

नाको ने अप्रैल, 2015 में आईएसओ प्रमाणन की विभिन्न प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नाको पहला प्रभाग/विभाग है जिसे आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय स्तर पर वयस्क एचआईवी व्याप्तता वर्ष 2001–03 में 0.38 प्रतिशत से वर्ष 2007 में 0.34 प्रतिशत तथा 2012 में 0.28 से वर्ष 2015 में 0.26 प्रतिशत की अनुमानित रफतार के साथ धीरे–धीरे कम हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर पुरूषों और महिलाओं में यही गिरावट देखी गयी।

दिसम्बर, 2015 तक 520 एआरटी केन्द्रों और 1074 लिंक एआरटी केन्द्रों के माध्यम से 9.41 लाख पीएलएचआईवी के लक्ष्य की तुलना में 9.19 लाख एचआईवी के साथ रह रहे लोग निःशुल्क एंटी–रेट्रोवायरल उपचार (एआरटी) प्राप्त कर रहे हैं। पीएलएचआईवी को मानसिक समाज सेवा प्रदान करने के लिए 350 परिचर्या और सहयोग केन्द्र (सीएससी) हैं।

उत्तरपूर्व राज्यों में एचआईवी/एड्स से जुड़े कार्यक्रम की जरूरतों की पूर्ति के लिए एक विशेष एचआईवी एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (सनराइज परियोजना) का प्रस्ताव किया गया है। इस दिशा में बुनियादी कार्य, परामर्श संबंधी चर्चा और क्रियाकलापों को अंतिम रूप देने का कार्य किया जा चुका है।

jk"Vªh; dSalj] e/kqesg] g`n;okfgdk vkSj vk?kkr fuokj.k ,oa fu;a=.k dk;ZØe ¼,uihlhMhlh,l½

आम गैर–संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम और प्रबंधन के लिए आयुष सुविधाओं तथा कार्य विधियों को एनपीसीडीसीएस सेवाओं के साथ एकीकृत किया जा रहा है। एनसीडी रोकथाम और उपचार के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में योग को बढावा दिया जा रहा है।

तृतीयक परिचर्या कैंसर केंद्र (टीसीसीसी) स्कीम के अंतर्गत राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई) और टीसीसीसी की स्थापना/सुदृढ़ीकरण की संकल्पना की गई है ताकि देश में व्यापक कैंसर परिचर्या प्रदान की जा सके। अब तक पांच (5) टीसीसीसी और छः (6) एससीआई अनुमोदित किए गए हैं और वर्ष 2015–16 के दौरान इस स्कीम के लिए 74 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

jk"Vªh; o`) LokLF; ifjp;kZ dk;ZØe ds rgr; d Lrjh; dk;Zdykiksa ds vUrxZr jk"Vªh; tjkoLFkk dsanz

केंद्र सरकार ने एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली और एक मद्रास मेडिकल कॉलेज (एमएमसी), चेन्नई में प्रत्येक में 97.75 करोड़ रु. की कुल लागत से दो राष्ट्रीय जरावस्था केंद्रों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की है।

प्रस्तावित केंद्रों से ऐसी आशा है कि ये देश में जरावस्था परिचर्या के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र होंगे। ये केंद्र (i) स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी; (ii) स्वास्थ्य व्यावसायिकों के प्रशिक्षण; (iii) 200 पलंग वाले अंतरंग सेवाओं के साथ अनुसंधानात्मक गतिविधियों में कार्य करेंगे।

jk"Vªh; n`f"Vghurk fu;a=.k dk;Zde

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2015–16 के दौरान मोतियाबिंद की लगभग 29.93 लाख शल्य क्रियाएं की गईं; स्कूल के बच्चों को लगभग 2.81 लाख निःशुल्क चश्में दिए गए और जनवरी, 2016 तक दान किए गए लगभग 28,122 नेत्र इकट्ठे किए गए।

bZ&xousZal

jk"Vªh; LokLF; iksVZy ¼,u,pih½% राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल में अनेक नई और मूल्य संवर्धित विशेषताएं शामिल की गई थीं। इसे स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में प्रामाणिक सूचना के एकल बिंदु स्रोत के रूप में सेवा प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। ऐसी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

- **,u,pih okW;l iksVZy%&** इसे स्वास्थ्य, रोगों, जीवनशैली, प्राथमिक चिकित्सा, डायरेक्टरी सेवाओं, स्वास्थ्य कार्यक्रमों आदि के विभिन्न मुद्दों से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय टॉल फ्री नंबर 1800–180–1104 के जरिए शुरू किया गया था। फिलहाल एनएचपी वॉयस पोर्टल स्वास्थ्य सूचना के लिए हेल्पलाइन के रूप में हिंदी, गुजरात, बांग्ला, तमिल और अंग्रेजी में सूचना का प्रचार–प्रसार कर रहा है।

- **,u,pih dh fy, eksckby ,Il%&** मोबाइल फोन के जरिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल डायरेक्टरी, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) द्वारा सहायता प्राप्त रक्त बैंकों, अस्पताल लोकेटरों आदि तक पहुंच बनाने के लिए एक एप्लीकेशन तैयार की गई है।

- **Rkckdw u'kkefDr dk;Zde ¼,e&LokLF; igy½&** एनएचपी डब्ल्यूएचओ के सहयोग से तंबाकू नशामुक्ति कार्यक्रम के लिए एक स्वास्थ्य पहल कार्यान्वित कर रहा है। इस पहल का शुभारंभ माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2016 को किया गया।

vkWuykbu iathdj.k iz.kkyh ¼vksvkj,l½% ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली की शुरूआत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत की गई। यह प्रणाली शुल्कों के भुगतान और अप्वाइंटमेंट, ऑनलाईन नैदानिक जांच रिपोर्टों, रक्त की उपलब्धता के संबंध में ऑनलाईन पूछताछ आदि में सुविधा प्रदान करती है। आज की तिथि के अनुसार, ओआरएस को एम्स– नई दिल्ली; एम्स– जोधपुर; एम्स– बिहार; आरएमएल अस्पताल; एसआईसी, सफदरजंग अस्पताल; निम्हांस; अगरतला राजकीय मेडिकल कॉलेज; जिपमेर जैसे बड़े अस्पतालों सहित 26 अस्पतालों में कार्यान्वित किया गया है। अब तक, लगभग 150,000 ऑनलाईन अप्वाइंटमेंट दिए गए हैं।

jk"Vªh; egRo dh laLFkku

वर्ष के दौरान मंत्रालय के तीन प्रमुख संस्थानों, नामतः एम्स, नई दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ और जिपमेर पुद्दुचेरी पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। कुछ प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:

,El] ubZ fnYyh%

- दिनांक 4 जुलाई, 2015 को डिजिटल भारत सप्ताह के भाग के रूप में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एम्स ई–अस्पताल परियोजना (ऑनलाईन पंजीकरण प्रणाली) की शुरूआत की गई।

- माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2015 को "कायाकल्प–स्वच्छ और हरित एम्स" की शुरूआत की गई।

- कैंसर के मरीजों को कम लागत की दवाइयां मुहैया कराने हेतु स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिनांक 15 नवंबर, 2015 को अमृत फार्मेसी और औषध भंडार का शुभारंभ किया गया।

- स्वास्थ्य मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 12 दिसंबर, 2015 को स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल परियोजना एम्स, झज्झर परिसर के "राष्ट्रीय कैंसर संस्थान" का भूमि–पूजन समारोह आयोजित किया गया।

- स्वास्थ्य मंत्री और विद्युत, कोयला और नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा दिनांक 25 दिसंबर, 2015 को एम्स ओपीडी ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का शुभारंभ किया गया।

- अगले 3–5 वर्षों में लगभग 3000 बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर एम्स की कुल बिस्तर क्षमता में व्यापक विस्तार।

- राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्झर में 2035 करोड़ रु. की लागत से कार्य आरंभ हुआ।

- 573 करोड़ रु. की लागत से एक नए ओपीडी ब्लॉक की स्थापना।

- 204.44 करोड़ रुपए की लागत से एक नया मातृ एवं बाल ब्लॉक।

- एक राष्ट्रीय जरावस्था केन्द्र।

- एमडी / डीएम / एमसीएच के नए पाठ्यक्रम तथा 90 प्रतिशत तक (250 से अधिक) सीनियर रेजिडेंटों के पदों में वृद्धि।

ih t hvkbl pMhx<%

- संगरूर में नया उपग्रही केन्द्र।
- ऑनलाइन रोगी पंजीकरण प्रणाली।
- एक व्यापक आपातकालीन और विकसित अभिघात केन्द्र।
- आंकोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, ईएनटी और हेपेटोलॉजी हेतु 250 बिस्तरों का एक नया ब्लॉक।

f t iej] innpjh%

- जिपमेर जन स्वास्थ्य इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना।
- बहु–विषयक विकसित अनुसंधान केन्द्र की स्थापना।
- स्तन संबंधी व्यापक परिचर्या केन्द्र की स्थापना।
- जरावस्था ब्लॉक की स्थापना।
- अतिविशेषज्ञता ब्लॉक का विस्तार।
- स्नातकोत्तर सीटों को 145 से बढ़ाकर 200 करना।

jk"Vh; LokLF; chek ;k t uk

विभाग व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना को एकीकृत करने की प्रक्रिया पर कार्य कर रहा है तब तक यह श्रम विभाग से ली गई आरएसबीवाई योजना को कार्यान्वित कर रहा है। योजना की कुछ प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं:

- आरएसबीवाई योजना को 19 राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है।
- 450 में से 397 जिलो को कवर किया गया है अर्थात् कुल जिलों का 86 प्रतिशत।
- 4.13 करोड़ परिवारों का नामांकन किया गया है, जोकि लक्षित 7.29 करोड़ परिवारों का 57 प्रतिशत है।
- वर्ष 2015–16 में पैनलबद्ध किए गए अस्पतालों की संख्या 10,680 है (6,290 निजी अस्पताल और 4390 सार्वजनिक अस्पताल)।
- 1 अप्रैल 2016 से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अतिरिक्त योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसकी लक्षित जनसंख्या 2 करोड़ है। यह योजना पात्र परिवार में प्रतिवर्ष प्रति वरिष्ठ नागरिक 30,000 रुपए का अतिरिक्त कवरेज प्रदान करेगी।

lkj

ऐसी आशा है कि ऊपर उल्लिखित पहल आगामी वर्ष में भी जारी रहेंगी; इस प्रकार सरकार अपने सभी नागरिकों को प्रभावी और समान रूप से किफायती और सुलभ स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में अग्रसर होगी।

(भानु प्रताप शर्मा)
सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग